

माननीय पीरेम चंद जैन और डीएस तेवतिया, जे.जे.

के समक्ष

1974 की सिविल रिट संख्या 1010। 20.8.1979 को

डी/डी

प्रकाश वूलन इंडस्ट्रीज - याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य - प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के लिए:- केएस कुंडू, एडवोकेट।

राज्य के लिए :- नौबत सिंह, सीनियर डीएजी, हरियाणा।

प्रतिवादी नंबर 2 के लिए: - ज्ञान सिंह, पीएस जैन और वीएम जैन, अधिवक्ता।

उत्तरदाताओं के लिए: - जी.सी. गर्ग, अधिवक्ता।

पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम, 1961 हरियाणा संशोधन अधिनियम, 1973 और 1979 द्वारा संशोधित, धारा 2 (ए), 5, 6, 8 और 23 - पंजाब कृषि उपज बाजार (सामान्य) नियम 1962, नियम 30 (1) भारत का संविधान 1950, अनुच्छेद 14 और 301-धारा 23 में आने वाली अभिव्यक्ति 'प्रसंस्करण के लिए लाई गई' का अर्थ है एक कृषि वस्तु का ऐसा व्यवहार करना जिससे इसे उपभोज्य बनाया जा सके जबकि वस्तु पर्याप्त रूप से समान रहती है - निर्माण को छोड़ दें - एक अभिन्न पार्टी निर्माण बनाने वाली प्रसंस्करण अधिनियम की धारा 23 के तहत बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हो सकती है बिक्री, खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए लाइसेंस रखने वाला डीलर इस तरह के अनुसार परिवर्तनशील नहीं है - डीलरों के एक वर्ग को सेवा प्रदान करने वाली बाजार समिति - अन्य डीलरों से प्राप्त धन की पर्याप्तता की दलील और अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता उपलब्ध नहीं है एक डीलर के लिए जो अपने दायित्व का विरोध करता है - राज्य के बाहर से आयातित माल पर शुल्क लगाना भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं करता है - शुल्क के उद्ग्रहण के अधीन प्रसंस्करण के लिए लाया गया कृषि उत्पाद - धारा 5 और 6 के तहत अधिसूचनाएं आवश्यक नहीं हैं।

[पैरा 7, 9, 20, 21, 24, 26, 27, 32 और 33 ]

## निर्णय

डी एस तेवतिया, जे। -

प्रश्न जो मुख्य रूप से इन रिट याचिका संख्या 1010, 1323, 1373, 1379, 4984, 5170, 5178 से 5181, 5265, 5332, 5378, 5475, 5914 और 6886 में विचार के लिए आता है; 284, 1320, 1975 का 6605, 6834, 6835, 6841, 6842, 7041 और 7449; 1976 का 121; और 1836, 1842, 1907, 1908, 1951, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 1979 की रिट याचिका (सिविल) सं 1952, 1955 से 1959, 1962, 2020, 2021, 2085 और 2263 (सभी 42 रिट याचिकाओं में) के रूप में यह है कि क्या याचिकाकर्ताओं की स्थिति में डीलरों पर बाजार शुल्क वैध रूप से लगाया जा सकता है जो कथित रूप से विनिर्माण के लिए कृषि उपज की विभिन्न वस्तुओं को बाजार क्षेत्र में लाते हैं।

दो. याचिकाकर्ताओं द्वारा सैंतीस रिट याचिकाओं को प्राथमिकता दी जाती है जो ऊनी धागे और कंबल के निर्माण के लिए उन लाते हैं, तीन उन लोगों द्वारा पसंद किए जाते हैं जो चावल को छीलने और बनाने के लिए धान लाते हैं, एक डीलर द्वारा जो पोल्ट्री फीड बनाता है; और दूसरा एक डीलर द्वारा जो दाल बनाने के लिए चना लाता है। चूंकि कानून का प्रश्न जो विचार के लिए आता है, सभी रिट याचिकाओं के समान है, एक सामान्य आदेश प्रस्तावित है।

तीन. प्रस्तुत प्रश्न से निपटने से पहले, इस मामले से निपटने वाले कानून का एक संक्षिप्त इतिहास ध्यान देने योग्य है। 7 मई, 1973 तक, मण्डी समितियां केवल अधिसूचित क्षेत्र में लाइसेंसियों द्वारा खरीदी या बेची गई कृषि उपज पर ही शुल्क लगा सकती थीं और अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में लाइसेंसियों द्वारा प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज पर ऐसा कोई शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं होता था। पंजाब कृषि उपज बाजार अधिनियम (1961 का पंजाब अधिनियम संख्या 23) की धारा 23, जिसे इसके बाद अधिनियम कहा जाता है, जैसा कि हरियाणा राज्य में लागू किया गया था, जो उस समय धारा को चार्ज कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में था:

"23. समिति, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में खरीदे या बेचे गए कृषि उत्पाद पर यथामूल्य आधार पर ऐसी दर से उद्ग्रहण कर सकेगी जो प्रत्येक एक सौ रुपए के बदले पचास नए पैसे से अनधिक की दर से होगी:-

बशर्ते कि -

(अ) किसी ऐसे लेन-देन के संबंध में कोई फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी जिसमें खरीदे या बेचे गए कृषि उत्पाद का वितरण वास्तव में नहीं किया जाता है; और

(आ) एक शुल्क केवल एक लेनदेन के लिए पार्टियों पर लगाया जाएगा जिसमें वितरण वास्तव में किया जाता है।

अधिनियम की धारा 23 को 1973 के पंजाब कृषि उपज बाजार (हरियाणा संशोधन) अधिनियम संख्या 21 द्वारा संशोधित किया गया था और तब यह निम्नानुसार था: -

"23. समिति, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएं, प्राधिकृत क्षेत्र में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा खरीदे गए या बेचे गए या प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि

उत्पाद पर प्रति एक सौ रुपए के लिए दो रुपए से अनधिक की दर से यथामूल्य आधार पर फीस उद्ग्रहण कर सकेगी:-

बशर्ते कि प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के मामले को छोड़कर -

(अ) किसी ऐसे लेन-देन के संबंध में कोई फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी जिसमें खरीदे या बेचे गए कृषि उत्पाद का वितरण वास्तव में नहीं किया जाता है; और

(आ) एक शुल्क केवल एक लेनदेन के लिए पार्टियों पर लगाया जाएगा जिसमें वितरण वास्तव में किया जाता है।

धारा 23 में पूर्वोक्त संशोधन और उक्त संशोधन के परिणामस्वरूप बाजार-शुल्क की वसूली को रिट पक्ष के कुछ लाइसेंसधारियों द्वारा चुनौती दी गई थी, ऐसी रिट याचिकाओं में से एक 1974 की सिविल रिट संख्या 1010 है।

चार. ऐसी रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, 1973 के हरियाणा संशोधन अधिनियम 21 से प्रभावित अधिनियम की धारा 23 के संशोधन को 11 फरवरी, 1976 से हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 5 द्वारा वापस ले लिया गया था; लेकिन इसके तुरंत बाद अधिनियम की धारा 23 को 1979 के हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 19 द्वारा फिर से संशोधित किया गया और नवीनतम संशोधन के बाद, यह निम्नलिखित शब्दों में उभरता है :-

"23. समिति, ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाए जाएँ, अधिसूचित क्षेत्र में डीलरों द्वारा क्रय या विक्रय या प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद पर प्रत्येक एक सौ रुपए के लिए दो रुपए से अनधिक की दर से यथामूल्य आधार पर फीस उद्ग्रहीत कर सकेगी:

बशर्ते कि प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उत्पाद के मामले को छोड़कर -

(अ) किसी ऐसे लेन-देन के संबंध में कोई फीस उद्ग्रहणीय नहीं होगी जिसमें खरीदे या बेचे गए कृषि उत्पाद का वितरण वास्तव में नहीं किया जाता है; और

(आ) एक शुल्क केवल एक लेनदेन के लिए पार्टियों पर लगाया जाएगा जिसमें वितरण वास्तव में किया जाता है।

नवीनतम संशोधन के अनुसरण में लगाए जाने वाले बाजार शुल्क को कुछ रिट याचिकाओं में चुनौती दी गई है। इस नवीनतम संशोधन के परिणामस्वरूप, अधिनियम की धारा 23 को लगभग उस स्थिति में वापस लाया गया है जिसमें यह 1973 के हरियाणा संशोधन अधिनियम संख्या 21 द्वारा किए गए संशोधन के बाद खड़ा था, एकमात्र अंतर यह है कि पहले यह 'लाइसेंसधारक' थे जिन्हें बाजार-शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया गया था, जबकि नवीनतम संशोधन में, लाइसेंसधारियों की उक्त अभिव्यक्ति को डीलर अभिव्यक्ति से बदल दिया गया है। हालांकि, सभी रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता 'लाइसेंस' और 'डीलर' दोनों हैं और इसलिए, ऊपर देखी गई भिन्नता मामले की योग्यता के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है।

पाँच. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने अधिनियम की धारा 23 में होने वाली अभिव्यक्ति 'प्रसंस्करण के लिए लाया गया' की व्याख्या इस तरह से करने की मांग की है ताकि ऐसे डीलरों को बाहर रखा जा सके जो विनिर्माण

के लिए कृषि उपज लाते हैं।

छः. अधिनियम में प्रसंस्करण, और विनिर्माण अभिव्यक्तियों का प्रयोग किया गया है, लेकिन इनमें से किसी भी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया है कि अभिव्यक्ति 'प्रसंस्करण' और 'विनिर्माण' परस्पर अनन्य शब्द हैं और उपरोक्त विवाद के समर्थन में जेके *काँटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड बनाम भारत संघ बनाम भारत संघ और अन्य बनाम भारत संघ बिक्री कर अधिकारी, कानपुर और अन्य, (1965) 16 एस.टी.सी.*

सात. कॉर्पस ज्यूरिस सेकुंडम में इन दो शब्दों को दिए गए अर्थ का भी संदर्भ दिया गया है जो इन दो शब्दों को निम्नलिखित अर्थ देता है:

'प्रसंस्करण' का अर्थ (72 सीजेएस 976) -

"'प्रसंस्करण' एक लचीला शब्द है और उस चीज़ में रासायनिक या भौतिक परिवर्तनों को संदर्भित कर सकता है जिस पर कार्य किया गया है। इसे एक पाठ्यक्रम या संचालन की विधि के अर्थ के रूप में परिभाषित किया गया है; क्रियाओं, गतियों या घटनाओं की एक श्रृंखला; प्रगतिशील अधिनियम या निरंतर संचालन या उपचार; किसी कार्य पर लागू होने वाली क्रिया, ऑपरेशन या उपचार की विधि; ऑपरेशन की एक श्रृंखला जो कुछ परिणाम देती है। इसे कुछ विशेष प्रक्रिया या उपचार के अधीन अर्थ के रूप में भी परिभाषित किया गया है; बाजार के लिए निर्माण, विकास या तैयारी की प्रक्रिया के अधीन करने के लिए।

'विनिर्माण' का अर्थ (66 सी.जे.एस. 669) -

"'निर्माण' को कच्चे या तैयार माल से उपयोग के लिए लेखों के उत्पादन के रूप में परिभाषित किया गया है, इन सामग्रियों को नए रूप, गुण, गुण या संयोजन देकर, चाहे हाथ से श्रम या मशीनरी द्वारा; कच्चे या तैयार माल से उपयोग के लिए बनाई गई कुछ भी भी।

हमारा ध्यान श्री ओम प्रकाश गुप्ता बनाम वाणिज्यिक कर आयुक्त और अन्य, (1965) 16 एस.टी.सी. 935 की ओर भी आकर्षित किया गया। उस मामले में, कलकत्ता उच्च न्यायालय (एकल पीठ का निर्णय) इस सवाल पर विचार कर रहा था कि कपूर पाउडर को कपूर क्यूब्स में बदलने का मतलब निर्माण या प्रसंस्करण है या नहीं। उस मामले में यह तर्क दिया गया था कि जब तक प्रक्रिया के परिणामस्वरूप कच्चे माल को किसी अन्य रूप में परिवर्तित नहीं किया जाता है, जो रूपांतरण तब नहीं हुआ जब कपूर को कपूर पाउडर से क्यूब्स में बनाया गया था, यह पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम की धारा 2 (बी) के अर्थ में नहीं आता था, 1954. विवाद को रद्द करते हुए, बी.एन. महोदय, जे. ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से अभिव्यक्ति 'प्रक्रिया' की निम्नलिखित परिभाषा को अनुमोदित किया,

"एक निरंतर और नियमित कार्रवाई या कार्यों का उत्तराधिकार, एक निश्चित तरीके से हो रहा है या किया जाता है, और कुछ परिणाम की उपलब्धि के लिए अग्रणी।

और कहा कि -

"'प्रक्रिया' शब्द द्वारा चिंतन की गई गतिविधि सामान्य है, जिसमें केवल निरंतर और नियमित कार्रवाई या कुछ परिणाम की उपलब्धि के लिए अग्रणी कार्यों के उत्तराधिकार की आवश्यकता होती है, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि गतिविधि में कुछ सामग्री पर कुछ ऑपरेशन शामिल होना चाहिए ताकि इसे किसी अन्य सामान में परिवर्तित किया जा सके। मेरी राय में, पश्चिम बंगाल बिक्री कर अधिनियम, 1954 की धारा

2 (बी) में प्रयुक्त 'प्रक्रिया' शब्द का उपयोग सामान्य अर्थों में किया गया है। इस सामान्य अर्थ में भी इस न्यायालय द्वारा खोडाबक्स बनाम प्रबंधक, कैलेंडोनियन प्रेस, एआईआर 1954 कलकत्ता 484 के मामले में 'प्रक्रिया' शब्द की व्याख्या की गई थी।

पूर्वोक्त अर्थों और पूर्वोक्त निर्णयों के अनुपात पर विचार करने से यह निष्कर्ष निकलता है कि अभिव्यक्ति प्रसंस्करण 'जिस संदर्भ में इसका उपयोग किया गया है, जब तक कि अधिनियम जानबूझकर एक विशिष्ट अर्थ नहीं देता है, जैसा कि यह तब करता है जब यह 'कृषि उपज' को परिभाषित करता है जिसका अर्थ है 'सभी कृषि उत्पाद चाहे संसाधित हों या नहीं, जैसा कि इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है' (जैसा कि वर्तमान में दिखाया जाएगा), इसका अर्थ है 'किसी कृषि वस्तु का ऐसा व्यवहार करना जिससे कि इसे उपभोज्य बनाया जा सके जबकि वस्तु पर्याप्त रूप से समान रहे' जबकि विनिर्माण में मूल वस्तु को भिन्न उपयोग और विपणन योग्य चरित्र के साथ एक अलग वस्तु में बदलने की परिकल्पना की गई है जो मूल कृषि वस्तु से भिन्न और भिन्न हो।

आठ. ऐसी स्थिति होने के कारण, अधिनियम की धारा 23 के अनुसार किसी ऐसे डीलर की देयता का निर्धारण करने में कोई कठिनाई नहीं है जो केवल कृषि उत्पाद की किसी मद को कृषि उत्पाद में संसाधित करता है, और न ही दायित्व का निर्धारण उस डीलर के संबंध में कोई कठिनाई प्रस्तुत करता है जो सीधे प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद से विनिर्माण करता है। यह डीलर के दायित्व का निर्धारण है जो न केवल अंतिम रूप से संसाधित कृषि उपज से एक अलग उपभोज्य वस्तु का निर्माण करता है, बल्कि एक कच्चे कृषि उत्पाद को कृषि उपज के उपरोक्त आइटम में संसाधित करता है।

नौ. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया है कि ऐसे मामलों में जहां एक डीलर द्वारा स्थापित विनिर्माण प्रक्रिया एक अभिन्न है, इसमें एक डीलर जिस वस्तु का निर्माण कर रहा है, उसे कच्चे कृषि उपज के प्रसंस्करण के बिना निर्मित नहीं किया जा सकता है और डीलर की उक्त गतिविधि को दो अलग-अलग गतिविधियों में विभाजित नहीं किया जा सकता है- एक कृषि का प्रसंस्करण एक कृषि उपज में उत्पादन और इस तरह के एक प्रसंस्कृत कृषि उपज से एक अंतिम उत्पाद का निर्माण करने के लिए और मूल गतिविधि दी गई विनिर्माण प्रक्रिया के अधीन कृषि उपज की मूल वस्तु से अलग एक वस्तु के निर्माण की है, तो ऐसे डीलर को कृषि उपज को बाजार क्षेत्र के अंदर लाने के लिए नहीं ठहराया जा सकता है प्रसंस्करण के लिए। उपरोक्त विवाद को जेके कॉटन स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स कंपनी लिमिटेड के मामले में किए गए सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य के निम्नलिखित टिप्पणियों द्वारा रेखांकित करने की मांग की गई है।(सुप्रा):

"..... सूती वस्त्र निर्माण की चिंता के मामले में, कपड़ा अंततः बाहर निकलने से पहले कच्चा कपास विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरता है। कपास को साफ किया जाता है, कार्डेड किया जाता है, यार्न में काता जाता है, फिर कपड़ा बुना जाता है, रोल पर रखा जाता है, कैलेंडर रंगा जाता है और दबाया जाता है। इन सभी प्रक्रियाओं को एकीकृत प्रक्रियाओं के रूप में माना जाएगा और कपड़े के निर्माण में शामिल किया जाएगा। केवल कपड़ा बुनाई की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले सामानों को मानना मुश्किल होगा और पूर्वकाल प्रक्रियाओं में उपयोग किए जाने वाले सामान को कपड़े के निर्माण में उपयोग किए जाने वाले सामान के रूप में नहीं माना जाएगा.....

.....

हमारे फैसले में यदि कोई प्रक्रिया या गतिविधि माल के अंतिम निर्माण से इतनी अभिन्न रूप से संबंधित है कि उस प्रक्रिया या गतिविधि के बिना निर्माण, भले ही सैद्धांतिक रूप से संभव हो, व्यावसायिक रूप से अक्षम हो सकता है, तो नियम 13 में निर्दिष्ट प्रक्रिया या गतिविधि में उपयोग के लिए इच्छित सामान विशेष उपचार के लिए अर्हता प्राप्त करेगा।

पूर्वोक्त आधिकारिक घोषणा के मद्देनजर, हम मानते हैं कि एक डीलर, जो इस तरह के विनिर्माण के लिए कृषि उत्पाद लाता है, को अधिनियम की धारा 23 के संदर्भ में बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है।

दस. अब अगला सवाल जो विचारणीय है वह यह है कि याचिकाकर्ताओं में से किसे इस तरह के विनिर्माण के लिए कृषि उपज की वस्तुओं को लाने पर विचार किया जा सकता है। हमारे सामने 4 या 5 प्रकार के डीलर हैं। सबसे पहले वे जो ऊनी धागे और कंबल बनाने के लिए कच्चा ऊन लाते हैं। स्पष्टतः ऊनी धागा और कंबल कच्चे ऊन से भिन्न वस्तु है और इसलिए कच्चे ऊन से ऊनी धागे और कंबल का विनिर्माण करने वाले ऐसे डीलर इस अधिनियम की धारा 23 के अनुसार बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

ग्यारह. डीलरों का अगला समूह वे हैं जो धान लाते हैं और चावल में उसी का प्रसंस्करण करते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है कि चावल एक निर्मित उत्पाद है और धान से अलग है। इस संबंध में उन्होंने गणेश ट्रेडिंग कंपनी, करनाल बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 1973 32 एस.टी.सी. 623 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह माना गया है कि चावल और धान दो अलग-अलग वस्तुएं हैं, चावल धान से अलग वस्तु है। हमारी राय में, बिक्री कर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के संदर्भ में दिए गए ये निर्णय याचिकाकर्ताओं के लिए किसी भी मदद का नहीं हो सकते हैं। वहां, अभिव्यक्ति 'विनिर्माण' को सामान्य सामान्य बोलचाल के शब्दों में माना जाता था क्योंकि अधिनियम में उक्त अभिव्यक्ति के लिए कोई विशिष्ट अर्थ नहीं था। यहां ऐसा नहीं है। वर्तमान मामले में, किसी को 'कृषि उपज' की परिभाषा को देखना होगा जिसे अधिनियम की धारा 2 (ए) में निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया गया है:

"2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(अ) कृषि उत्पाद से कृषि, बागवानी, पशुपालन या वन की सभी उपज अभिप्रेत है चाहे वह प्रसंस्कृत हो या नहीं, जैसा कि इस अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है।

यह देखने के लिए कि कृषि उत्पाद क्या है, हमें परिभाषा के आधार पर अनुसूची पर भी विचार करना होगा। अनुसूची में धान और चावल दोनों का उल्लेख किया गया है। परिभाषा के साथ अनुसूची को पढ़ने पर, कोई भी अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंच जाएगा कि चावल को संसाधित धान के रूप में माना जाता है, हालांकि आम बोलचाल में चावल धान से अलग एक वस्तु है। अतः अधिनियम की धारा 23 के प्रयोजन के लिए चावल को प्रसंस्कृत कृषि मद माना जाएगा और इसलिए प्रसंस्करण के लिए धान को चावल में लाने पर अधिनियम की धारा 23 स्पष्ट रूप से कवर होगी जिससे ऐसे व्यापारी को मण्डी शुल्क का भुगतान करना पड़ता है।

बारह. उपरोक्त दृष्टिकोण को मेसर्स प्रेम चंद राम लाल बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ के निर्णय से समर्थन प्राप्त है। पंजाब राज्य और अन्य, 1970 पी.एल.जे. उस मामले में यह तर्क दिया गया था कि गुर, शक्कर और खंडसारी 'कृषि उत्पाद' निर्मित वस्तुएं नहीं थीं और चूंकि 'कृषि उत्पाद' की ये निर्मित वस्तुएं अनुसूची में शामिल हैं, इसलिए अनुसूची और 'कृषि उत्पाद' की परिभाषा



"अपीलकर्ताओं का यह भी तर्क है कि चूंकि गुर और शक्कर निर्मित उत्पाद हैं, इसलिए वे अधिनियम की धारा 2 (ए) के अर्थ के भीतर कृषि उपज की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं। धारा 2 (ए) कृषि उपज को परिभाषित करती है जिसका अर्थ है 'कृषि, बागवानी, पशुपालन या वन के सभी उत्पाद चाहे संसाधित हों या नहीं, जैसा कि इस अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट है, जिसमें वस्तुओं की 95 वस्तुओं का उल्लेख है। ये धारा 2 (ए) के तहत वैधानिक रूप से कृषि उत्पाद हैं। इस तर्क पर विचार करना संभव नहीं है कि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इन मदों की न्यायिक संवीक्षा करेगा कि क्या ये कृषि उत्पाद हैं अथवा नहीं। धारा 2 (ए) में परिभाषा के मददेनजर ऐसी जांच जगह से बाहर है। इस संदर्भ में हम यह नोट कर सकते हैं कि धारा 38 के तहत राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा अनुसूची में कृषि उत्पाद की किसी अन्य मद को जोड़ सकती है या ऐसी किसी भी निर्दिष्ट वस्तु को संशोधित या हटा सकती है। कृषि उपज की अनुसूची मदों में जोड़ने की इस शक्ति के कारण ही धारा 2 (क) के तहत परिभाषा का पहला भाग मार्गदर्शन देता है कि कृषि उत्पाद का क्या अर्थ है। इसलिए, प्रस्तुतियाँ सार से रहित हैं।

फिर, कपास की स्थिति समान है, कपास के लिए, दोनों जीना या सुन्न और बनौला (कपास-बीज) को कृषि उत्पाद के रूप में माना जाता है और इसलिए, बिक्री कर अधिनियम के तहत दिए गए निर्णय, जिसमें बनौला को कपास से अलग एक निर्मित वस्तु के रूप में माना गया है, याचिकाकर्ताओं के लिए कोई फायदा नहीं होगा। *रघबीर चंद सोम चंद बनाम आबकारी और कराधान अधिकारी, भटिंडा, और अन्य, (1960) 11 एसटीसी 149* में, ओटाई और बिना कपास को एक ही पदार्थ माना गया है, जैसा कि उनके लॉर्डशिप के निम्नलिखित अवलोकन से स्पष्ट होगा:

"..... हालांकि, जिनिंग की प्रक्रिया का संचालन करने वाले व्यक्ति का मामला बहुत अलग है। वह उसी तरह का काम करता है जो आदमी करता है, जो गेहूं साफ करता है और उसे थैलियों में डालता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, वह कपास-बीज प्राप्त करता है जो एक अलग वस्तु है, लेकिन ओटाई की हुई कपास केवल बिना कपास के समान है, सिवाय इसके कि यह निर्माता द्वारा उपयोग के लिए अधिक तैयार है। एक वस्तु को ऐसी स्थिति में रखना कि इसे निर्माण के लिए अधिक आसानी से उपयोग किया जा सके, लगभग एक वस्तु को विपणन योग्य बनाने के समान बात; वस्तु वही रहती है और करती है किसी भी तरह से इसके चरित्र को न बदलें। इसलिए, मेरा विचार है कि अप्रकाशित और जिन्न कपास अनिवार्य रूप से एक ही चीज है .....

तेरह. हमारी राय में, चने को दाल में परिवर्तित करने वाले ऐसे डीलर चने को बाजार क्षेत्र में लाने के लिए बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, क्योंकि चने को दाल में बदलने का अर्थ ग्राम को दाल में प्रसंस्कृत करना नहीं है, बल्कि यह चना दाल से दाल का निर्माण है जो चने से भिन्न वस्तु है और आम बोलचाल में भी, दाल को चने के नाम से नहीं जाना जाता है।

चौदह. मक्का और अन्य कृषि उत्पादों को पोल्ट्री फीड में बदलने वाले डीलरों की भी यही स्थिति होगी। मक्का और अन्य अवयवों के मिश्रण और रूपांतरण के बाद प्राप्त पोल्ट्री फीड नामक वस्तु अपने अवयवों से पूरी तरह से अलग एक वस्तु है और इसलिए, मक्का, जौ आदि को मुर्गी पालन में परिवर्तित करने के लिए बाजार क्षेत्र में लाना अधिनियम की धारा 23 के अनुसार ऐसी वस्तुओं के कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण नहीं माना जा सकता है।

पंद्रह. तथापि, खोल टूटने के बाद मुंगफली दाना (मुंगफली बीज) प्राप्त करना मुंगफली दाना के विनिर्माण



के समान नहीं होगा, क्योंकि अधिनियम मुंगफली और मुंगफली दाना को प्रसंस्कृत और असंसाधित दोनों प्रकार से कृषि उत्पाद मानता है और इसलिए मुंगफली को बाजार क्षेत्र में लाना इसके प्रसंस्करण के लिए लाने के समान होगा न कि विनिर्माण के लिए।

सोलह.गर्ग ने कुछ मामले दायर किए थे जिसमें डीलरों ने आरोप लगाया था कि वे तेल बनाने के लिए मुंगफली और मस्टर बीज ला रहे थे। इन मामलों को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया था, लेकिन श्री गर्ग को हस्तक्षेप करने की अनुमति दी गई थी और इसलिए, ऐसे डीलरों की देयता से भी निपटा जाता है।

सत्रह. जहां तक तेल उत्पादन के लिए तिलहन लाने का संबंध है, हमारे विचार से यह विनिर्माण के लिए वस्तु लाने के समान होगा क्योंकि तेल एक ऐसी वस्तु है जो उस कच्चे कृषि उत्पाद से बहुत भिन्न और भिन्न है जिससे इसे निकाला जाता है।

अठारह. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि, किसी भी मामले में, प्रदान की गई सेवा के लिए बाजार-शुल्क लगाया जा सकता है और चूंकि डीलरों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाती है, जिनके पास अपवाद के बिना उनके कारखाने हैं, जिनमें वे कृषि उपज को संसाधित करते हैं, प्रमुख बाजार यार्ड के बाहर, इसलिए कोई क्विड प्रो क्वो नहीं होने के कारण लगाए जाने वाले शुल्क को शुल्क नहीं बल्कि कर माना जा सकता है। याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने केवल कृष्ण पुरी और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1985 आरआरआर 173 (एससी): 1977 का सीए 1083, 4 मई, 1979 को एक अधिसूचित बाजार क्षेत्र में लाइसेंसधारियों द्वारा खरीदे या बेचे गए कृषि उपज पर वैध लेवी के लिए परीक्षणों को संतुष्ट करने के लिए निर्णय लिया गया।

"(1) वसूल की गई फीस की राशि अधिसूचित बाजार क्षेत्र में लाइसेंसधारियों को सेवाएं प्रदान करने के लिए निर्धारित की जानी चाहिए और इसका एक अच्छा और पर्याप्त हिस्सा अपने उद्देश्य के लिए खर्च किया जाना दिखाया जाना चाहिए।

(दो) लाइसेंसधारियों को प्रदान की गई सेवाएं कृषि उपज की खरीद या बिक्री के लेनदेन के संबंध में होनी चाहिए।

(तीन) कि विपणन विधान के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से खरीद और बिक्री के लेन-देन को सुविधाजनक बनाने के प्रयोजन से बाजार क्षेत्र में सेवाएं प्रदान करते समय लाइसेंसियों को संपूर्ण लाभ प्रदान करना आवश्यक नहीं है लेकिन उन्हें कुछ विशेष लाभ अवश्य प्रदान किए जाने चाहिए जिनका प्रत्यक्ष रूप से उपयोग किया जाता है। लाइसेंसधारियों और लेनदेन के बीच घनिष्ठ और उचित सहसंबंध।

(चार) कि लाइसेंसियों को कुछ विशेष लाभ प्रदान करते समय बाजार में ऐसी सेवाएं प्रदान करने की अनुमति है जो बाजार में होने वाले लेन-देन से संबंधित सभी संबंधितों के सामान्य हित में हों।

(पाँच) कि कृषि उत्पाद को बढ़ाने के प्रयोजन के लिए बाजार शुल्क की राशि खर्च करना, गांवों में इसकी परिवहन सुविधा और किसानों के लाभ के लिए मुख्य रूप से या विशेष रूप से अन्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए इस आधार पर अनुमति नहीं दी जाती है कि लंबे समय में ऐसी सेवाएं बाजार में लेनदेन की मात्रा को बढ़ाने के लिए अंततः व्यापारियों को भी लाभान्वित करती हैं। व्यापारियों को ऐसा अप्रत्यक्ष और दूरस्थ लाभ किसी भी अर्थ में उनके लिए विशेष लाभ नहीं है।

(छः) कि क्विड प्रो क्वो का तत्व अंकगणितीय सटीकता के साथ स्थापित करना संभव नहीं हो सकता है, या यहां तक कि आवश्यक भी हो सकता है, लेकिन यहां तक कि मोटे तौर पर और यथोचित रूप से यह

उन अधिकारियों द्वारा स्थापित किया जाना चाहिए जो शुल्क लेते हैं कि यह राशि उन लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए खर्च की जा रही है जिन पर शुल्क का बोझ पड़ता है।

(सात) फीस के रूप में एकत्र की गई राशि का कम से कम एक अच्छा और पर्याप्त हिस्सा, दो-तिहाई या तीन-चौथाई के पड़ोस में हो सकता है, जिसे उचित निश्चितता के साथ दिखाया जाना चाहिए क्योंकि ऊपर उल्लिखित प्रकार की सेवाएं प्रदान करने के लिए खर्च किया जा रहा है।

उपर्युक्त दूसरे और तीसरे मानदंड पर जोर देते हुए, यह तर्क दिया गया था कि लाइसेंसधारियों को प्रदान की गई सेवाएं प्रसंस्करण के लेनदेन के संबंध में होनी चाहिए और यह सेवाएं लाइसेंसधारियों को कुछ विशेष लाभ प्रदान करने वाली होनी चाहिए, जिनका एक ओर लाइसेंसधारियों और दूसरी ओर लेनदेन के बीच प्रत्यक्ष, घनिष्ठ और उचित सहसंबंध हो।

उन्नीस. हमसे पहले सभी लाइसेंसधारियों के पास कृषि उपज की बिक्री, खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण से संबंधित व्यावसायिक गतिविधि करने के लिए लाइसेंस थे। संशोधन से पहले बाजार शुल्क केवल कृषि उत्पादों की बिक्री और खरीद पर लगाया जाता था न कि भंडारण और प्रसंस्करण पर। संशोधन के बाद मंडी क्षेत्र में प्रसंस्करण के लिए लाई गई कृषि उपज पर शुल्क लगाने की मांग की गई। तथापि, कृषि उत्पादों के भण्डारण पर अभी तक ऐसा कोई शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं है। विचारणीय प्रश्न यह उठता है कि क्या उस व्यक्ति के मामले में बाजार शुल्क की उगाही की मात्रा अलग-अलग होगी जो कृषि उपज की बिक्री, खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण से संबंधित सभी चार व्यावसायिक गतिविधियों को करता है और एक डीलर जो एक या दो या केवल तीन ऐसे क्रियाकलाप करता है।

बीस. जब एक मण्डी समिति डीलरों को सेवा प्रदान करने का प्रावधान करती है तो वह ऐसा इस दृष्टिकोण से करती है कि जिन डीलरों ने कृषि उत्पाद से संबंधित उपर्युक्त चारों क्रियाकलापों में व्यवसाय करने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर लिए हैं, वे स्वयं को संलग्न करेंगे और इसलिए किसी व्यक्तिगत डीलर को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि यद्यपि उसके पास बिक्री के उपर्युक्त सभी चार प्रकार के क्रियाकलापों में संलग्न होने का लाइसेंस था, खरीद, भंडारण और प्रसंस्करण लेकिन, वास्तव में, ऐसी गतिविधियों में से केवल एक या दो को ही किया जाता था और इसलिए वह उस व्यक्ति की तुलना में कम बाजार शुल्क का भुगतान करेगा जो बिक्री, खरीद, भंडारण और कृषि उपज के प्रसंस्करण की सभी चार गतिविधियों में लगा होगा। इसलिए, हमारी राय में, एक डीलर जो प्रसंस्करण के लिए कृषि उत्पाद लाता है, उसे यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि यद्यपि वह कृषि उत्पाद की खरीद और बिक्री का काम करेगा और उक्त लेनदेन पर बाजार शुल्क का भुगतान करेगा, वह प्रसंस्करण के लेनदेन पर बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि उसे प्रसंस्करण का लेन-देन। मोरेसो, इस कारण से कि किसी दिए गए मामले में, कृषि उपज को संसाधित करने के बाद एक डीलर को कृषि उपज का निपटान करना होगा। यह, वह प्रिंसिपल मार्केट-यार्ड या सब-मार्केट यार्ड में ऐसा करेगा; लेकिन प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद को बेचते समय, ऐसे प्रसंस्कृत कृषि उत्पाद की बिक्री और खरीद के लेन-देन पर कोई बाजार शुल्क नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि उक्त कृषि उत्पाद पर शुल्क पहले ही लगाया जा चुका था जब इसे डीलर द्वारा प्रसंस्करण के लिए लाया गया था, जो अब उसकी बिक्री को प्रभावित करेगा और पंजाब कृषि उत्पाद बाजार (सामान्य) नियमावली के नियम 30, 1962, परिकल्पना करता है कि -

"30. (1) कृषि उपज से विनिमत या निकाले गए किसी कृषि उत्पाद के विक्रय या क्रय पर, जिसके संबंध में ऐसी फीस उसी अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में या राज्य के भीतर किसी अन्य अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में पहले ही संदत्त कर दी गई है, कोई मण्डी फीस उद्ग्रहीत नहीं की जायेगी।

ऐसे मामले में, हालांकि डीलर ने उन सेवाओं का उपयोग किया था जो विक्रेता और खरीदार को प्रदान की जाती हैं, फिर भी वह प्रदान की गई सेवाओं के लिए किसी भी शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

20-ए. बाजार समिति की ओर से यह दावा किया गया है कि बाजार समिति अन्य बाजारों में प्रचलित दरों के बारे में जानकारी की आपूर्ति पर अपने धन का खर्च करती है। इसने गोदामों और विश्राम गृहों की भी स्थापना की है जिनका उपयोग उन डीलरों द्वारा किया जा सकता है जो प्रसंस्करण के लिए कृषि उपज लाते हैं।

इक्कीस. डीलर के पास कृषि उपज के भंडारण के लिए पर्याप्त जगह नहीं हो सकती है, हालांकि वह ऐसे समय में खरीद से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में कृषि उपज खरीदने के लिए अधिक इच्छुक हो सकता है जब कृषि उत्पादों की कीमतें बढ़ने की संभावना है। ऐसे मामले में, यदि बाजार समिति के गोदाम उपलब्ध हैं, तो डीलर पर्याप्त मात्रा में कृषि उत्पादों को खरीदने और उनमें भंडारण करने में सक्षम होगा और इस प्रकार अपने व्यवसाय में लाभ अर्जित करेगा जो एक व्यवसायी के लिए मुख्य गतिविधि है। इस तरह की सेवा सीधे डीलर को लाभान्वित करती है और प्रसंस्करण के लिए कृषि उपज लाने के लेनदेन के साथ इसका एक निश्चित संबंध है।

बाईस. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने केवल कृष्ण पुरी और एक अन्य मामले (सुप्रा) में सुप्रीम कोर्ट की निम्नलिखित टिप्पणियों की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया

"..... भविष्य में यदि बाजार शुल्क को 2 रुपये प्रति सौ रुपये की दर से अधिक बढ़ाने की मांग की जाती है, तो इस निर्णय के आलोक में उचित बजट, अनुमान, तुलन-पत्र, जो हाथ में और जमा में धन का शेष दिखाते हैं, आय और व्यय का अनुमान आदि सावधानीपूर्वक तैयार किए जाने चाहिए। जैसा कि हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया था, यह हो सकता है कि बाजार समितियों या बोर्ड के लिए तुलन-पत्र तैयार करना अनिवार्य नहीं है क्योंकि उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा की जाती है लेकिन बाजार शुल्क में और वृद्धि करने के प्रयोजनार्थ तुलन-पत्र बजट और अनुमानों के साथ-साथ स्थिति की सही तस्वीर प्रस्तुत करेंगे। तभी, और केवल तभी, एक कानूनी औचित्य हो सकता है या बाजार शुल्क की दर को उचित सीमा तक और बढ़ा दिया जा सकता है।

और आग्रह किया कि उपर्युक्त टिप्पणियों का निहितार्थ यह था कि बाजार प्रतिबद्धताओं को या तो बाजार-शुल्क की दर में वृद्धि करके या अधिक डीलरों को बाजार-शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाकर अतिरिक्त धन जुटाने से प्रतिबंधित किया गया था, जब तक कि बाजार समिति को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता न हो और यह साबित करने के लिए कि उसे अतिरिक्त स्रोतों की आवश्यकता है, इसने एक बैलेंस शीट तैयार की थी जो इसके संसाधनों की सही तस्वीर पेश करती थी।

तेईस. इस बात पर और जोर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य ने उस मामले में पाया कि बाजार शुल्क के रूप में 2 रुपये लगाकर जुटाए गए संसाधन पर्याप्त थे, कोई भी बाजार शुल्क या तो प्रसंस्करण या भंडारण के लिए कृषि उपज लाने पर नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि बाजार समितियों को यह नहीं दिखाना था कि उन्हें अधिक धन की आवश्यकता थी।केवल कृषि उपज की बिक्री और खरीद पर बाजार शुल्क की लेवी को प्रतिबंधित करके प्राप्त करने में सक्षम।

चौबीस. हमें विद्वान वकील के इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिलती है। एक बार जब यह माना जाता है कि बाजार समिति दिए गए लेनदेन के संबंध में डीलरों के किसी दिए गए वर्ग को सेवा प्रदान कर

रही है, तो बाजार समिति मुआवजे की हकदार है और ऐसे डीलर को यह कहते हुए नहीं सुना जा सकता है कि अन्य डीलरों से समिति ने पर्याप्त बाजार शुल्क जुटाया था और इसलिए, वह, उसे प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में, बाजार समिति को किसी भी बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

पच्चीस. याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया अगला तर्क यह है कि राज्य के बाहर से बाजार समिति क्षेत्र में आयातित वस्तुओं पर बाजार शुल्क की वसूली भारत के संविधान के अनुच्छेद 301 के प्रावधानों का उल्लंघन करती है, जिसमें याचिकाकर्ता डीलरों के अधिकारों पर अनुचित प्रतिबंध लगाए गए हैं।

छब्बीस. यहां फिर से, हम याचिकाकर्ताओं की ओर से लिए गए रुख में कोई दम नहीं पाते हैं। डीलरों पर लगाया गया शुल्क याचिकाकर्ताओं की श्रेणी में आने वाले डियरल्स को प्रदान की गई सेवाओं के लिए क्षतिपूर्ति के रूप में है। इस तरह की लेवी याचिकाकर्ताओं के व्यापार करने के अधिकारों पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाती है। इस दृष्टिकोण को जीके कृष्णन आदि बनाम तमिलनाडु राज्य और अन्य, एआईआर 1975 सुप्रीम कोर्ट 589 में रिपोर्ट किए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले से समर्थन मिलता है, और निम्नलिखित टिप्पणियों को लाभ के साथ नोटिस किया जा सकता है:

"..... उस मामले में अपीलकर्ताओं ने राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1951 को लागू किया, इंटरअलिया,, अनुच्छेद 301 का उल्लंघन करने के रूप में। उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया और इस न्यायालय ने 4 से 3 के बहुमत ने माना कि अधिनियम वैध था और अपीलों को खारिज कर दिया। मामले ने विशेष रूप से निर्णय को खारिज कर दिया अतिबादी मामला (1961) 1 एससीआर 809 (एआईआर 1961 सुप्रीम कोर्ट 232), जहां तक यह माना जाता है कि यदि कोई राज्य विधायिका सड़कों को बनाए रखने के लिए आवश्यक धन जुटाने के लिए कर लगाना चाहती है, तो यह केवल मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही किया जा सकता है वही अनुच्छेद 304 (बी) में प्रदान किए गए राष्ट्रपति के रूप में। में ख्येरबारी टी कंपनी लिमिटेड वी। असम राज्य (1964) 5 एस.सी.आर. 975 कहा गया कि ऑटोमोबिल में अतियाबारी मामले में फैसले की पुष्टि की गई है एक स्पष्टीकरण के साथ मामला है कि नियामक उपाय या प्रतिपूरक कर लगाने के उपाय करते हैं अनुच्छेद 301 में अपेक्षित प्रतिबंधों के दायरे में नहीं आते हैं और इस तरह के उपायों को अनुच्छेद 304 (बी) के प्रावधानों की आवश्यकता का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। में कोई इसे जिस भी तरीके से चुन सकता है, ऑटोमोबाइल में बहुमत के निर्णय का प्रभाव मामला यह है कि एक प्रतिपूरक कर व्यापार के आंदोलन भाग पर प्रतिबंध नहीं है और वाणिज्य ".

याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने आगे प्रस्तुत किया कि प्रसंस्करण के लिए लाए गए कृषि उपज पर बाजार-शुल्क लगाने से पहले, बाजार समिति पर यह निर्भर था कि वह उस संबंध में एक अधिसूचना जारी करे, जैसा कि अधिनियम की धारा 5 और 6 द्वारा परिकल्पित है। इस संबंध में, उन्होंने अमर सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1968 पी.एल.आर. 909 में रिपोर्ट किए गए इस न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले पर भरोसा किया।

सताईस. अधिनियम की धारा 5 और 6 के प्रावधान निम्नलिखित शब्दों में हैं: -

"5. राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे कृषि उपज की खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण पर और ऐसे क्षेत्र में जो अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जा सकता है, नियंत्रण करने के अपने इरादे की घोषणा कर सकती है। ऐसी अधिसूचना में यह उल्लेख होगा कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाने के लिए कम

से कम तीस दिनों की अवधि के भीतर राज्य सरकार द्वारा प्राप्त की जाने वाली किसी भी आपति या सुझाव पर विचार किया जाएगा।

(1) धारा 5 के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात् और ऐसी आपतियों और सुझावों पर विचार करने के पश्चात् जो ऐसी अवधि के समाप्त होने से पहले प्राप्त हों, राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा और किसी अन्य रीति से, जो विहित की जाए, धारा 5 या उसके किसी भाग के अधीन अधिसूचित क्षेत्र को कृषि के संबंध में इस अधिनियम के प्रयोजन के लिये अधिसूचित मण्डी क्षेत्र घोषित कर सकेगी। धारा 5 या उसके किसी भाग के तहत अधिसूचित उत्पादन।

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

उपर्युक्त प्रावधानों के अवलोकन से पता चलता है कि इसके लिए केवल अधिसूचना में अधिसूचित दिए गए क्षेत्र के संबंध में ऐसे कृषि उत्पाद की खरीद, बिक्री, भंडारण और प्रसंस्करण पर नियंत्रण रखने के संबंध में विचारों और आपतियों का पता लगाना आवश्यक है और यह कि आपतियां, यदि कोई हों, सुनने के बाद, यदि कोई हो, राज्य सरकार अधिनियम की धारा 6 के अधीन धारा 5 या उसके किसी भाग के अधीन अधिसूचित दिए गए क्षेत्र को अधिनियम के प्रयोजन के लिए अधिसूचित मण्डी क्षेत्र घोषित करेगी। धारा 5 में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'ऐसे कृषि उत्पाद के क्रय, विक्रय, भण्डारण और प्रसंस्करण पर नियंत्रण रखना' को अधिनियम की धारा 8 के उपबंधों के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो निम्नलिखित शब्दों में हैं:

"8. (1) धारा 6 के अधीन अधिसूचना जारी करने की तारीख के पश्चात् या ऐसी बाद की तारीख से, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए, कोई भी व्यक्ति, जब तक इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा छूट प्राप्त न हो, अधिसूचित बाजार क्षेत्र के भीतर अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति या राज्य सरकार की ओर से क्रय के लिये किसी स्थान को स्थापित, स्थापित या जारी रखने या जारी रखने की अनुमति नहीं देगा, कृषि उत्पाद का विक्रय, भंडारण और प्रसंस्करण अथवा क्रय, विक्रय, भण्डारण अथवा प्रसंस्करण, केवल इस अधिनियम के उपबन्धों, इसके अधीन बनाए गए नियमों तथा उपविधियों तथा अनुज्ञप्ति में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार प्रदत्त लाइसेंस के अधीन ही नहीं है।

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

\* \* \* \* \*

जब इस प्रकार पढ़ा जाता है, तो कोई भी इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुंचता है कि प्रभावित पक्षों के विचारों का पता लगाया जाता है कि क्या ऐसे कृषि उत्पाद के संबंध में राज्य सरकार को किसी दिए गए क्षेत्र में अधिनियम की धारा 8 में परिकल्पित प्रकार का नियंत्रण रखना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसलिए, किसी दिए गए लेनदेन पर बाजार शुल्क लगाने के लिए ऐसी कोई अधिसूचना प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है पार्टियां प्रभावित हुईं।

अठ्ठाईस. अमर सिंह (सुप्रा) का मामला, जिस पर याचिकाकर्ताओं की ओर से भरोसा किया गया है, एक ऐसा मामला था जिसमें राज्य सरकार ने अधिनियम की धारा 38 के तहत अपनी शक्तियों के अनुसरण में

कृषि उपज की कुछ वस्तुओं को जोड़कर अनुसूची में परिवर्धन किया, जो इससे अनुपस्थित थे। उसमें उठाया गया तर्क यह था कि अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत अधिसूचना जारी करने से पहले ऐसी वस्तुओं को नहीं जोड़ा जा सकता था। इस प्रकार दिए गए तर्क को निरस्त कर दिया गया और यह माना गया कि अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत अधिसूचना जारी करना राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 38 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूची में मदों को जोड़ने के लिए पूर्ववर्ती शर्त नहीं थी। हालांकि, यह जोड़ा गया था कि कृषि उपज की नई जोड़ी गई वस्तुओं में सौदा करने के लिए कृषि उपज की नई जोड़ी गई वस्तुओं के संबंध में डीलरों को लाइसेंस लेने के लिए बुलाने से पहले, अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत एक अधिसूचना जारी की जानी चाहिए।

उन्तीस. उस मामले में निर्धारित कानून के पूर्वोक्त प्रस्ताव के साथ कोई झगड़ा नहीं है। वर्तमान मामले में, जैसा कि पहले ही देखा गया है, सभी याचिकाकर्ताओं के पास न केवल खरीद, बिक्री, भंडारण और निर्माण की गतिविधियों में संलग्न होने के लिए लाइसेंस थे, बल्कि दिए गए बाजार क्षेत्र के संबंध में प्रसंस्करण के लिए कृषि उपज लाने के लिए भी, अधिनियम की धारा 23 में संशोधन के परिणामस्वरूप आयाम को न तो कम किया गया है और न ही बढ़ाया गया है ताकि व्यापारिक समुदाय के विचारों का पता लगाने की आवश्यकता हो और अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत अधिसूचना जारी करके प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित किया जाता है।

तीस. अंत में, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जिस सीमा तक बाजार शुल्क की लेवी केवल राज्य के बाहर से बाजार क्षेत्र में लाई गई उपज पर लगाई जाती है, न कि राज्य के भीतर से किसी दिए गए बाजार क्षेत्र में लाए गए कृषि उत्पाद पर, यह दो प्रकार के उत्पादों के बीच भेदभाव करता है और, इसलिए, चरित्र में भेदभावपूर्ण है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

इक्तीस. एक बात के लिए इस तरह के विवाद का कोई आधार नहीं है क्योंकि अधिनियम की धारा 23 के संदर्भ में ऐसा कोई अंतर नहीं है, लेकिन तर्क के लिए यह मानते हुए कि ऐसा अंतर किया जाता है, तब भी, हमारी राय में, विवाद में कोई योग्यता नहीं है।

बतीस. भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में दावे से निपटते समय, यह दोहराना उचित है कि, अब तक, देश के सर्वोच्च न्यायिक मंच द्वारा आधिकारिक रूप से स्थापित किया गया है कि विधायिका, संघ या राज्य, समान रूप से स्थित लोगों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं कर सकती है, लेकिन साथ ही विधायिका को वर्गीकृत करने का अधिकार दिया जाता है (ग) विधान के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और यह देखते हुए कि इस प्रकार के विभेदीकरण का उसके द्वारा किए गए इस प्रकार किए गए वर्गीकरण द्वारा प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य के साथ संबंध है। इसलिए, पूर्वोक्त घोषणा के आलोक में, किसी को यह देखना होगा कि क्या हरियाणा राज्य विधानमंडल राज्य के बाहर से किसी दिए गए बाजार क्षेत्र में आयातित कृषि उपज पर बाजार शुल्क के अधीन होकर भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

तैंतीस. प्रश्नाधीन संविधि का उद्देश्य बाजार समिति द्वारा डीलरों को प्रदान की गई सेवाओं की प्रतिपूत डीलर के दिए गए लेन-देन पर या ऐसे लेनदेन में लगे डीलर पर बाजार शुल्क लगाकर करना है। यदि कोई डीलर कृषि उत्पाद के प्रसंस्करण के लेन-देन में लगा हुआ है और यदि यह माना जाता है, जैसा कि निर्णय के पहले भाग में हमारे द्वारा किया गया है, कि बाजार समिति ऐसे डीलर को सेवा प्रदान करती

है, तो बाजार समिति को इस प्रकार प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रतिपूत के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वह कृषि उत्पाद जिसे वह राज्य के बाहर से प्रसंस्करण के अपने व्यवसाय को चलाने के लिए आयात करता है या राज्य के भीतर सारहीन है। हालांकि, यदि यह माना जाता है कि प्रसंस्करण के लिए डीलर द्वारा राज्य के बाहर से आयातित माल राज्य के बाहर से प्रसंस्करण के लिए लाए गए माल पर बाजार शुल्क की वसूली से बच जाएगा और डीलर राज्य के बाहर से प्रसंस्करण के लिए सभी सामान खरीदने का फैसला करता है, तो वह उक्त समिति के बावजूद बाजार समिति को बाजार शुल्क का भुगतान करने से पूरी तरह से बच जाएगा उसे सेवा प्रदान करना और इसलिए, ऐसे डीलर को प्रदान की गई सेवाओं के लिए खुद को क्षतिपूर्ति करने के लिए बाजार समिति को अक्षम करना। इस तरह की व्याख्या कानून के उद्देश्य के खिलाफ जाएगी। इसलिए, हमारी राय में, वर्तमान मामले में राज्य के बाहर से किसी दिए गए बाजार क्षेत्र में लाई गई उपज पर बाजार-शुल्क लगाने से इस कारण से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है कि राज्य के बाहर से बाजार क्षेत्र में आयातित माल और राज्य के भीतर किसी दिए गए बाजार क्षेत्र से आयातित सामान उसी श्रेणी में नहीं आते हैं, उसमें जब माल खरीदे जाने के बाद राज्य के भीतर से प्रसंस्करण के लिए किसी दिए गए बाजार क्षेत्र में लाया जाता है, तो वे पहले से ही राज्य में खरीद और बिक्री के लेनदेन के समय बाजार शुल्क के अधीन थे, जबकि राज्य के बाहर से आयातित माल उनके आयात से पहले राज्य के भीतर बाजार शुल्क के अधीन नहीं थे और लाए जाने पर पहली बार इस तरह से अधीन थे प्रसंस्करण के लिए।

चौंतीस. पूर्वोक्त कारणों से, हम मानते हैं कि ऐसे डीलर जो प्रसंस्करण के लिए राज्य के बाहर से किसी दिए गए बाजार क्षेत्र में कृषि उत्पाद लाते हैं, न कि विनिर्माण के लिए, अधिनियम की धारा 23 के संदर्भ में बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं।

पैंतीस. हमारे पूर्वोक्त निष्कर्षों के मद्देनजर, डीलर-याचिकाकर्ता जो ऊनी धागे और कंबल के निर्माण के लिए कच्चा ऊन लाते हैं (1974 का सिविल रिट संख्या 1010, 1323, 1373, 1379, 4984, 5170, 5178 से 5181, 5265, 5332, 5914; 1975 का 1320, 6605, 6834, 6835, 6841, 6842, 7041, 7449; 1976 का 121; 1842, 1907, 1908, 1951, 1952, 1955 से 1959, 1979 की सिविल रिट संख्या 2344 में हस्तक्षेप करने वाले के मामले में या 1979 की सिविल रिट संख्या 2344 में हस्तक्षेप करने वाले के मामले में या चना (1974 की सिविल रिट संख्या 5575) या पोल्ट्री फीड (1979 की सिविल रिट संख्या 1836) के निर्माण के लिए तिलहन या तेल निर्माण के लिए तिलहन अधिनियम की धारा 23 के दायरे से बाहर होंगे और इसलिए, उपरोक्त विनिर्माण उद्देश्यों के लिए बाजार क्षेत्र में उनके द्वारा लाए गए कृषि उपज के संबंध में किसी भी बाजार शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसलिए, ऐसे डीलरों द्वारा दायर रिट याचिकाओं की अनुमति दी जाती है और यह भी आदेश दिया जाता है कि पहले से भुगतान किया गया बाजार शुल्क बाजार समिति द्वारा याचिकाकर्ताओं को वापस कर दिया जाएगा। 1974 की संख्या 5378 और 6886 और 1975 की 284 (चावल में धान के प्रसंस्करण से संबंधित) वाली अन्य रिट याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं। हालांकि, हम पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ देते हैं।

**प्रेमचंद जैन, जे. -में सहमत हूँ।**

तदनुसार आदेश दें।

अस्वीकरण: स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

Checked By:

Sakshi Gupta

Trainee Judicial Officer

Chandigarh Judicial Academy

□